भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2733 का उत्तर

राजस्थान में धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना

2733. श्री भजन लाल जाटव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) उक्त परियोजना पर कार्य कब प्रारंभ किया गया था और इसे किस समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था;

(ग) कार्य स्वीकृति आदेश और डीपीआर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त रेल परियोजना के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजना पर व्यय की गई राशि, पूरे हो चुके कार्य और शेष कार्य का प्रतिशत के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त परियोजना का शेष कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(छ) उक्त परियोजना किस रेल मंडल के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ज) कार्य पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(झ) धौलपुर से बाड़ी और सरमथुरा से तांतपुर रेल लाइन का कार्य किस तारीख को प्रारंभ किया गया था;

(ञ) उक्त लाइन पर कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ट) उक्त रेल लाइनों के लिए क्रमश: कितनी राशि स्वीकृत की गई है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ट): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंकों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्द्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फारवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राजस्थान राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 51,814 करोड़ रुपये लागत की 4,191 कि.मी. कुल लंबाई की 32 रेल परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 05 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,183 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 14,785 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	15	1230	134	3593
आमान परिवर्तन	5	1252	759	5398
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	1709	290	5794
कुल	32	4191	1183	14786

राजस्थान राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों का बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रुपए/वर्ष
2024-25	9,959 करोड़ रुपये (14 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान राजस्थान राज्य मे पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	798 कि.मी.	159.6 कि.मी./वर्ष
2014-24	3,742 कि.मी.	374.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

गंगापुर सिटी (144.6 कि.मी.) तक विस्तार के साथ धौलपुर-सिरमुत्तरा आमान परिवर्तन/नई लाइन की परियोजना की योजना दो चरणों में बनाई गई है।

प्रथम चरण में, उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाले धौलपुर-बारी-मोहरी-सिरमुत्तरा (69.10 कि.मी.) का आमान परिवर्तन कार्य मार्च, 2022 में 746.83 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। परियोजना में अब तक 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

दूसरे चरण के लिए, सिरमुत्तरा-गंगापुर सिटी नई लाइन (75.50 कि.मी.) के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को स्वीकृत दी गई है। मोहरी-तांतपुर (18 कि.मी.) आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकृत परियोजना नहीं है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओँ पर निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना

की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी अवं वन्यजीव संबंधी मंजूरी हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों को हल करना शामिल है। इससे वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओँ में राज्य सरकार द्वारा लागत के हिस्से को जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/ओं विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करता है।

*****